RAJYA SABHA

Wednesday, the 30th November, 1977/ the 9th Agrahayana, 1899 (Saka)

The House met at Eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

Oral Answers to Questions

*301. [*The questioners (Shri Deorao Patil, Shri R. D. Jagtap Avergoankar and Shri Krishnarao Narayan Dhulap) were absent. For answer.* vide col. 39-40 infra.]

Termination of Services of C G.H.S. Doctors

*302 SHRI HIMMAT SINH:
DR. V P DUTT:†
SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH:
SHRI JAGJIT SINGH ANAND:
SHRI SAWAISINGH SISODIA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have terminated or decided to terminate the services to thousands of C G.H S doctors;

(b) if so, what are the details in this regard and what are the reasons therefor,

(c) what is the average length of service of these doctors under the CGHS;

(d) in what manner Government propose to fill the resultant vacancies; and

(e) what steps Government have taken to provide alternate employment to these doctors?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) से (ड) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए 679 कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है । इन अधिकारियों को भर्ती तथा नियुक्ति के समय स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि जब तक यह पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये डाक्टरो से नही भर लिये जाते तब तक के लिए यह बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था है । इनमे से 1975 से 1977 तक के वर्षो में 400 तदर्थ डाक्टरों को नियुक्त किया गया था । संघ लोक सेवा आयोग के नियमित डाक्टरो के आने पर अपान स्थिति के दौरान भर्ती किए गए केवल उन्ही तदर्थ डाक्टरों की सेवाएं समाप्त की जा रही है जिनके सगठनों मे उन्हें खपाने के लिए कोई स्पष्ट खाली पद उपलब्ध नही है । ऐसी सम्भावना है कि 1975 से पहले नियुक्त कोई भी तदर्थ डाक्टर फिलहाल छंटनी का शिकार नही होगा । सघ लोक सेवा आयोग से नियमित आधार पर नियुक्त डाक्टरो के आने मे जिन तदर्थ डाक्टरो को हटना पड़ रहा है, उनको भी फिलहाल बाहरी इलाकों में वैकल्पिक नौकरी की पेशकश की जा रही है ।

शुरू 1978 मे जिन वर्तमान रिक्त पदो को भरने के लिए चयन किए जाने का प्रस्ताव है, उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन निकाले है, उन पर ये बर्खास्त किए गए तदर्थ डाक्टर फिर से आवेदन कर सकते है ।

‡[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (e) A Statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

There are about 679 Junior Medical Officers appointed on *ad-hoc* basis

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. V. P. Dutt.

‡[ ] English translation.

with a clear understanding both at the time of recuritment as well as appointment that this was purely a temporary arrangement until such time as these posts were filled by regular appointees to be recommended by the Union Public Service Commission. Out of these there was an intake of about 400 *ad-hoc* appointees during the years 1975—77. The services of only such *ad-hoc* appointees who were recruited during emergency are being terminated on being replaced by regular UPSC candidates, if there were no other clear vacancies available to absorb them in the same organisation. No *ad-hoc* appointees who joined earlier than 1975 are expected to face retrenchment for the time being. Even those *ad-hoc* appointees who are displaced by UPSC nominees are being offered alternative jobs in outlying areas for the time being.

The displaced *ad-hoc* appointees can also apply afresh in response to UPSC advertisements for filling in the existing vacancies in respect of which selections are proposed to be held early 1978.]

DR. V. P. DUTT: You are well aware of the fact that some of our brightest students go into the medical profession and that they get probably the longest and the most intensive training in any profession in this country. And yet, a large number of people appointed through duly constituted selection committees on an *ad hoc* basis have been given notices of termination of their service. I underline the words 'duly constituted selection committees' that is, boards of competent experts. Therefore, it is not as if these people are below qualifications; these are people who have been trained through the norms laid down by the medical associations.

I am sorry, the hon. Minister of Health and Family Welfare is not here; he would have provided some heat, if not light. I would like to ask: Is it not a fact that the UPSC by a letter dated 18-6-77 had laid down certain guidelines? The first part of those guidelines was—

> "It has been decided that the candidates if any working on an *ad hoc* basis in your organisation in fulfilment of the bond already executed with the Government may be allowed to continue on an *ad hoc* basis irrespective of the length of the service and need not be replaced by the regular officers."

Has this guideline been already violated or not in the case of a number of people? I would also ask whether it is not a normal practice that a person is kept on probation only for one year or for a maximum of two years? Therefore, I would ask what is the number of people who are now being thrown out of jobs, who have put in more than 2 years of service and whether you are not violating your own guideline by giving them termination notices.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन् तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए 679 कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को भर्ती तथा नियुक्ति के समय स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि जब तक यह पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये डाक्टरों से नहीं भर लिये जाते तब तक के लिए यह बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था है। इनमे से 1975 से 1977 तक के वर्षों में 400 तदर्थ डाक्टरो को नियुक्त किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के नियमित डाक्टरों के आने पर आपातस्थिति के दौरान भर्ती किये गये ....

MR. CHAIRMAN: He does not want that information at all.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, वे तो हीट चाहते हैं। मै उनको हीट दे दूंगा ...

(*Interruptions*)

DR. V. P. DUTT: The hon. Minister is replying even without listening to the question.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मैंने यह बताया है कि 1975 से 1977 तक के वर्षो मे 400 डाक्टर तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये थे। चूकि उन्होने अपने सवाल मे यही बात पूछी है, इसलिए मै यह जवाब दे रहा हू। सघ लोक सेवा आयोग से नियमित डाक्टरो के आने पर आपातस्थिति के दौरान भर्ती किए गए केवल उन्ही तदर्थ डाक्टरो की सेवाए समाप्त की जा रही है जिन सगठनो मे उन्हे खपाने के लिए कोई स्पष्ट खाली पद उपलब्ध नही है। श्रीमन, मै यह भी सूचना देना चाहता हू कि अभी तक जो डाक्टर हटाये गये है उनकी सख्या सिर्फ 16 है।

DR V P DUTT Sir, he has not answered my first question

MR CHAIRMAN The hon Minister may reply to two supplementaries first, whether the guidelines laid down by the Public Service Commission have been violated or not That is what he wants to know

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसबारे मे जो नियम दिये है, वह इस समय मेरे पास नही है लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एडहाक है, उन सब को लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा, और उसमे उनका निर्णय किया जायेगा कि कौन लिया जा सकता है और कौन नही लिया जा सकता है। रिटिन एक्जामिनेशन के बारेमे लोक सेवा आयोग ने इसलिये लिखा है क्योकि पहले साल भर मे केवल 50 से 100 डाक्टर लिये जाते थे लेकिन इमरजेन्सी मे एक साल मे 400 डाक्टर लिये गये। जो अप्वायंटमेन्ट किये गये वह हजारो की सख्या मे थे। इसलिये उन्होने रिटिन एक्जामिनेशन और ओरल दोनो लिये। इसमे सिर्फ यह बात निकली।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND What about the other question?

MR CHAIRMAN. Please wait, I am here. Then he asked about the probationary period.

श्री राजनारायण : जो एडहाक अप्वायन्ट मेन्ट हुआ है, इसके बारे मे सदन मे पहले भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार किसी को निकालना नही चाहती। प्वाइट यह है कि कुछ लोग इमरजेन्सी पीरियड मे लिये गये, 400 डाक्टर लिये गये। अब हम लोगो ने पब्लिक सर्विस कमीशन से बात की है। वह कहते है कि हम एक्जामिनेशन उनका लेगे। पहले चार सबजेक्ट मे लेते थे, अब केवल एक सबजेक्ट मे लेगे। पहले सर्जरी, मेडीसन, प्रसूति चिकित्सा और रोगो की रोकथाम इन चारो विषयो पर देना पडता था। लेकिन इसमे उनको रियायत दी गई है। हमने कहा कि क्योकि वे हमारी सर्विस मे है, इसलिये हम उनको निकालना नही चाहते। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बात को मान लिया है कि हम एक विषय मे ही, जिस विषय मे वे चाहे, परीक्षा दे दे। यदि पास हो जायेगे तो उनको रखा जायेगा और यदि पास नही होगे तो नही रखा जायेगा।

DR V P DUTT Sir, my first question was whether the guidelines have been

MR CHAIRMAN. That is all right.

DR V P DUTT violated or not. There is no answer to that

MR CHAIRMAN Put your second supplementary

DR V P DUTT Yes, I would like to

श्री राजनारायण : श्रीमन्, . .

MR CHAIRMAN Let him say It is recorded there Why do you get up?

डा० विद्या प्रकाश दत्त : यदि आप चाहते है तो नही पूछता साहब, मैं बैठ जाता हू।

श्री राजनारायण : नही, आप पूछिये।

DR. V. P. DUTT: I was going to appeal to you to take a human view of it, and not associate it with Emergency as such.

MR. CHAIRMAN: He has already replied correctly.

DR. V. P. DUTT: I would like, firstly, to ask whether the figure given by the hon. Minister of State is correct that only 16 people have been removed My information from all the newspaper reports is that a large number is involved. Secondly, arising from it, I would like to ask whether the normal procedure in such cases is that those who are appointed last are the first to be given termination notices. If so, is it not a fact that in a number of cases, that has been violated? I do not want to mention individual cases. In the Willingdon Hospital, there is the case of Dr. Arora. There are other cases, but I do not want to mention them There have been violations of the guidelines and also violations in various cases of the assurances given by the hon Minister.

श्री राजनारायण : श्रीमान, मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि सदन के सम्मानित सदस्य जब यहां आते हैं तो पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दे दिये गये रहते है, उनको पढ़ने की कृपा नही करते, तकलीफ नही उठाते। मैं गाइड लाइन जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी है, उसको बता रहा हूं.....

DR. V. P. DUTT: Sir, I have read everything.

श्री राजनारायण : आप कृपया बैठिये। मैं यह कह रहा हू कि 'पब्लिक सर्विस कमीशन का मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए' तो इस मानवीय दृष्टिकोण की जो वकालत की है, हमारे दोस्त ने, चाहे उनका खुद मानवीय दृष्टीकोण न हो, मगर हमारी सरकार का मानवीय दृष्टिकोण है और इसी मानवीय दृष्टिकोण के कारण ही जो इमरजेंन्सी के दौरान हुआ है, उनको हटाने के लिये वह कहते थे कि उनको चारों परीक्षाओं मे बैठना पड़ेगा। हमारी तरफ से तो सब के साथ समान व्यवहार किया जाना है। एक विषय मे सबको बैठना पड़ेगा, यह गाईड लाइन्ज है। एक विषय मे अगर वे पास हो जाएंगे तो किसी को नहीं हटाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे माननीय सदस्य दत्ता साहब चाहते है कि Quacks should be appointed. No. The Government is not going to appoint quacks.

DR. V. P. DUTT: Sir, on a matter of personal explanation...

SHRI RAJNARAIN: Sir, I am on my legs...

DR V. P. DUTT: Sir, I have not made any such statement. Why is the Minister getting into the habit of imputing statement to us? I have not made any such statement.

MR. CHAIRMAN: No, no. You have not made any such statement. Now, Rajnaraiji, you please reply to the question The House is satisfied...

श्री राजनारायण : उन्होने जो एक बात कही कि हजारों निकाले गए, यह मेरी समझ मे नही आता। मुझे बडी खुशी है कि आप सैटिसफाईड है, हाउस सैटिसफाइड है। आप कृपा करके एक मिनट का समय दे दीजिए और मैं सम्मानित सदस्य को सैटिसफाई कर दू। कही पर भी नही निकाले गए, अखबारों की गप्प पर सम्मानित सदस्य न चले। मैंने पहले बता दिया है कि ऐसे डाक्टर कुल 679 हैं जिनको परीक्षा मे बैठना है अत इससे ज्यादा का तो सवाल ही पैदा नही होता। इसलिए हल्ला करने से कोई मतलब नही है। हल्ला करके, चापलूसी करके कोई लाभ नही है, अब इंदिरा गाधी के पास वह ताकत नही रह गई है ..

(Interruptions)

श्रीमती हामिदा हबीबबुल्लह : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछ न

चाहती हू कि आज ही अखबारो मे यह खबर छपी है कि एक बडी तादाद मे सीनियर स्पेशिलिस्टस को जूनियर स्पेशलिस्ट की जगह पर रिवर्ट कर दिया गया है । यह आज ही अखबार मे निकला है । मै मत्री महोदय से पूछना चाहती हू कि क्या यह खबर सच्ची है । खबर यह है कि

"Over 12 specialists in four hospitals run by the Muncipal Corporation face threat of reversion to lower posts As many as 10 specialists have been reverted over the last year" They were reverted over the last one year

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव . श्रीमन् यह सवाल तो इससे सबधित नही है । जूनियर सीनियर की बात नही है । इसके लिए अगर एक दूसरा नोटिस दे दे ता इसकी सूचना . .

MR CHAIRMAN Not that She just wanted to know whether it is not the practice that the person who comes first should be the last to go or the person who comes last should go first There is no need for a separate question Have you any information or not?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप समझ गए, सारा सदन समझ गया कि हमारे यहा लास्ट इज गा फर्स्ट वाला प्रिसिपल नही चलेगा । हमारे यहा तो प्रिसिपल यह चल रहा है कि जो लोग परीक्षा मे बैठेगे वे परीक्षा मे पास हो जाएगे चाहे कोई लास्ट हो या फर्स्ट हो, किसी का नही निकाला जाएगा ।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND Sir, our first difficulty is that things appear first in the newspapers and then statements are made It was reported in all the newspapers that thousands of doctors were being thrown out Now the Minister says, 'No' Then, why did he not contradict the Press report earlier? Now a new thing has appeared and the Minister does not seem to know that I would only request the honourable Minister to read the report which appeared in the Press today and then clarify what the situation is. And that is the point which the lady Member has asked Sir, what does the Minister say in the printed answer supplied at the Table? He says 679 were recruited and they were—on an *ad hoc* basis They were all on a purely temporary basis Amongst them the services of 400 who were recruited during the Emergency are being terminated I am going by what they have said in the statement. Now my question is this There were many misdeeds done during the Emergency I would be one with the Minister in condemning those misdeeds If during the Emergency these appointments were made by-passing all norms, by-passing the guidelines, by-passing the experience which the people got, by-passing the duration of probation that they worked on, then, instead of all those who were appointed, that is, instead of all the 679, why are only 400 appointed during the Emergency—being discriminated against? I would request the honourable Minister kindly to tell us what the urgent necessity was for such purely temporary appointments for which they are now being told that their services would be dispensed with When there is such a dearth of qualified doctors in our country, why should these doctors not have been absorbed? And then, in the statement the Minister says, "Even those *ad hoc* appointees who are displaced by UPSC nominees are being offered alternative jobs in outlying areas for the time being" So, there is a definite sign of discriminatory behaviour just because emergency was involved What was wrong with the emergency is being sought to be maintained and this is a negative attitude

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आपने पहले ही संकेत कर दिया कि सदन समझ गया । मगर हमारे सम्मानित सदस्य पता नही क्यों उसको रिपीट कर रहे है । मैं बडी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हं मान लीजिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षाएं लेता है ।

और उससे परीक्षा में पास डाक्टर्स निकलकर आते हैं तो उनको हम कहीं रखेंगे या नहीं रखेंगे । अच्छा, अगर हम उनको रखेंगे तो वह प्रिंसिपल वहां एप्लाई होगा या नहीं कि last come should go first. अगर वह होगा तो इमरजेंसी के अन्दर जो भर्ती हुई है तो लास्ट निकालने की बारी उनकी आयेगी । मगर हमारी ओर से कोशिश हो रही है ऐसी व्यवस्था की कि किसी को न निकालना पड़े । परन्तु अगर निकाले जाये तो हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते है ।

SHRI B. V. ABDULLA KOYA: It has been said that out of these, there was an intake of about 400 *ad hoc* appointees during the year 1975—77 and the services of only such *ad hoc* appointees who are recruited during the emergency are being terminated. In fact it has been reported to us that the services of so many who do not come under this category are also being terminated. Another thing is that in a letter of the Ministry of Health and Family Welfare it has been said:

> "It has been decided that the bonded candidates, if any, working on *ad hoc* basis, in your organisation, in fulfilment of the bond already executed by them with the Government, may be allowed to continue on *ad hoc* basis irrespective of their length of service...."

But I find that some of the Doctors whose period of bonded service has not been completed are also being asked to go away. Therefore, I would like the Minister to tell me whether, if such specific complaints are reported to him personally, he will take the trouble of seeing that such Doctors are retained in service.

श्री राजनारायण : श्रीमन् माननीय सदस्य ने अपना जो सवाल किया उसका उत्तर भी खुद अपने से ही दे दिया । देखा जाय कि पहले जो सामान्य लोगों के मस्तिष्क में बात है कि जो आखिर में भर्ती हो पहले निकाला जाय, उसके मुताबिक जो एक जनरल सरक्यूलर गया, मगर हम लोगों की यह बराबर कोशिश रही कि ऐसी स्थिति हो कि उनको भी न निकालना पड़े । इसलिए हमने दूसरी बात यह की कि उनके कुछ टर्म्स है जो उन्होंने भरे है, कुछ कंडीशन्स पर दस्तखत है, अगर उनके दस्तखत हों भी फिर भी हम कोशिश कर रहे है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था निकाले जिससे कि उनको खपाया जा सके ।

SHRI B V. ABDULLA KOYA: The Public Service Commission will take another two or three years and by that time they will be thrown out and they will lose all their services.

श्री राजनारायण : एक बात सदन को समझ लेनी चाहिए कि यह हमारा ही मंत्रालय ऐसा है जो पब्लिक सर्विस कमीशन से करीब करीब दूसरे तीसरे विषयों पर भी बात करता है । उन्होंने एक व्यवस्था बनादी है कि जल्दी से जल्दी वह परीक्षा करने जा रहे है विदिन 2-3 मन्थस । जो हमारी बात हुई चेयरमेन से उन्होंने कहा हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो यह जल्दी से जल्दी होगी । मगर हमारे सम्मानित सदस्य इस बात को माने हुए हैं कि जो आखिर भर्ती हुआ है अगर जाना ही होगा तो वही पहले जायेगा । (*Interruptions*) और हर जगह हम लोगों ने रैफल क्ल दूसरी जगह सारे रास्ते निकाल लिए । (*Interruptions*) अब हमारे लर्नेड एक्स सेक्रेटरी जो खड़े हुए है उनको मौका दीजिए ।

SHRI B. N. BANERJEE: My question is very simple. Am I correct in understanding that the policy of the Government and particularly of the Health Ministry is that none of the *ad hoc* appointees should, as far as possible, be thrown out and their decision is that if any of these per-

sons, whether recruited before or during the emergency, pass in one of the subjects as decided in consultation with the Public Service Commission, they are quite safe? I think they are quite safe and their services will not be terminated Is my understanding correct?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव आपका सोचना सही है इसीलिए मन्त्री जी ने साफ कर दिया है कि 4 विषयो मे से अगर एक विषय मे भी पास हो जाते है, चाहे कोई भी, तो उनको रख लिया जाएगा, उनको हटाया नही जाएगा ।

DR M M. S SIDDHU: Sir, I thought that the main interest of the House would be the care of the patients rather than of the doctors in service Do you want a better type of doctors or a doctor who does not fulfil the conditions laid down? Sir, I am also a Member of the Medical Council of India and we know that there are institutions in which the standards are not satisfactory Now, this being the case, may I ask the honourable Minister whether they would give them another chance to appear in the examination, I mean, those people who have not been selected, so that they have a chance to refresh their knowledge? Secondly, Sir, may I also request the honourable Minister to lay the comments of the team of experts who have interviewed them so that the House may be enlightened on the knowledge that these candidates possess? I have information with me from one of the persons who was there as an expert that some of the candidates or students were not quite up to the mark

MR CHAIRMAN: It is a suggestion for action which the Ministry may consider. Mr Rajnarain, you need not reply.

श्री राजनारायण श्रीमन, उनकी एक बात का जबाब दे द । माननीय सदस्य चूंकि डाक्टर भी है और ये डाक्टरी पेशे मे कुशल है, ये हमारे स्वास्थ्य मत्रालय की अनेक कमेटियो से भी सबधित है, दिल्ली के अस्पतालो की देखरेख की कमेटी उनकी सदारत मे बन रही है, उन्होने बहुत सही कहा है कि बहुत से डाक्टर अप टु द मार्क नही है । उनको इसकी जानकारी है । मगर एक मानवीय दृष्टि है, और वह मानवीय दृष्टि डाक्टर के लिए भी होगी, रोगी के लिए भी होगी, कि ऐसा डाक्टर न रहे कि जो रोगी की दवा करके मार ही डाले । तो दोनो तरफ से हमारी मानवीय दृष्टि है ।

श्रीमन् एक और सूचना दिए देता हूं जो मेरे पास अभी आई है, कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमारे दफ्तर को सूचित कर दिया है कि Examination for selection in the month of March-April, 1978 लिया जा रहा है, ताकि उनका कौतूहल शात हो ।

MR. CHAIRMAN· Next question.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, many doctors have been penalised . .

MR. CHAIRMAN: That is all right I have called the next question.

श्री राजनारायण चेयरमन साहब, आप श्रीमती अम्बिका सोनी से कह दे वे खुद हमारे यहा कार्यालय मे आ जाएं और जानकारी ले ।

श्रीमती अम्बिका सोनी आ जाऊगी ।

Outstanding bills of contractors pending with the DDA for payment

*303. SHRI PIARE LAL KUREEL URF PIARE LAL TALIB:
SHRI JAGDISH JOSHI:†
SHRI IBRAHIM KALANIYA:
SHRI KHURSHED ALAM KHAN:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at present outstanding bills of contractors

†The question was actually asked on the floor of the House by **Shri** Jagdish Joshi.